आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 10 लखनऊ, रविवार 14 जून 2026 से 20 जून 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस-स्लोवाकिया यात्रा आज से शुरू, रणनीतिक साझेदारी, नवाचार और जी–७ में भारत की भूमिका पर रहेगा फोकस

नई दिल्ली।'' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी १३ से १८ जून २०२६ तक फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा का उद्देश्य यूरोप के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने प्रस्थान से पहले जारी अपने वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत की रणनीतिक ष्टि में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया गया है। नीस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ होने वाली बैठक में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी १४ जून को नीस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम भारत–फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय स्टार्टअप्स, उच्च शिक्षा संस्थानों और वैश्विक निवेशकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी १४–१५ जून को स्लोवाक गणराज्य की राजकीय

यात्रा करेंगे। वर्ष १९९३ में स्लोवाकिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी। ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान व्यापार, निवेश और भारत– यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। स्लोवाकिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी १६ और १७ जून को एवियां में आयोजित होने वाले जी–७ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह लगातार आठवां अवसर होगा जब भारत को जी–७ बैठक में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जी–७ में भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती से रखेगा और विश्व के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों पर अपने विचार साझा करेगा। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी १८ जून को पेरिस में आयोजित VivaTech २०२६ में हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में भारत का राष्ट्रीय मंडप सबसे बड़ा होगा, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाएगा। प्रधानमंत्री पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की यह यात्रा यूरोप और जी–७ देशों के साथ भारत के संबंधों को नई मजबूती देगी तथा वैश्विक स्तर पर सहयोग के नए अवसर खोलेगी।

ECI की राष्ट्रीय कार्यशाला में यूपी के मीडिया नोडल अधिकारियों ने सीखी चुनावी संचार की बारीकियां, ३५० से अधिक अधिकारियों ने लिया प्रशिक्षण

लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर की एक दिवसीय कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के मीडिया नोडल अधिकारियों ने भी सहभागिता कर चुनावी संचार व्यवस्था, मीडिया प्रबंधन और सोशल मीडिया रणनीतियों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला में देश के सभी ३६ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मीडिया नोडल अधिकारी, सोशल मीडिया नोडल अधिकारी तथा उन राज्यों के जिला मीडिया नोडल अधिकारी और जिला जनसंपर्क अधिकारियों ने भाग लिया, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण का तीसरा चरण चल रहा है या आगामी चुनाव प्रस्तावित हैं। इस महत्वपूर्ण आयोजन में ३५० से अधिक मीडिया एवं संचार विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की मौजूदगी में संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हाल में संपन्न पांच राज्यों के चुनावों में आजादी के बाद से जनभागीदारी का ऐतिहासिक स्तर देखने को मिला है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनाव से संबंधित सभी संचार समयबद्ध, सरल भाषा में और तथ्यों एवं कानून के आधार पर होने चाहिए। निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने प्रभावी संचार पर जोर देते हुए कहा

कि केवल सूचना पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके प्रभाव का आकलन कर उसे अधिकतम करना भी जरूरी है। वहीं निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने अधिकारियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आयोग के नियम, निर्देश और दिशा–निर्देश आम जनता तक आसान और स्पष्ट तरीके से पहुंचने चाहिए। कार्यशाला में चुनावी संचार रणनीति, मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतदान प्रक्रिया तक की जानकारी, ECINET के प्रभावी उपयोग, संवैधानिक प्रावधानों, संबंधित कानूनों, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और मीडिया समन्वय जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा प्रेस नोट तैयार करने, मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं के प्रभावी प्रसार, भ्रामक सूचनाओं (मिसइन्फ मेशन) और नकारात्मक नैरेटिव से निपटने, युवा मतदाताओं को जोड़ने और निर्वाचन आयोग की पहलों को जनता तक पहुंचाने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला ने विभिन्न राज्यों के अधिकारियों को अपने अनुभव साझा करने और बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान–प्रदान का अवसर भी प्रदान किया। उत्तर प्रदेश से सभी जिलों के मीडिया नोडल अधिकारियों ने इस राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इनमें अधिकांश जिला सूचना अधिकारी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश की मीडिया नोडल अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की विशेष कार्याधिकारी गरिमा स्वरूप ने भी कार्यशाला में हिस्सा लिया।

पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर छात्रों के बीच पहुंचेंगे राहुल गांधी, कोटा से शुरू होगा संवाद अभियान

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर देश के विभिन्न शहरों का दौरा करेंगे। पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर राहुल गांधी छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी ''१७ जून को राजस्थान के कोटा'', ''१० जुलाई को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज'', ''११ जुलाई को बिहार के पटना'' और ''१४ जुलाई को दिल्ली'' में छात्रों से मुलाकात करेंगे। इन संवाद कार्यक्रमों के दौरान छात्रों की समस्याओं भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक की घटनाओं और रोजगार के अवसरों जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की ओर से इसे युवाओं की

आवाज को प्रमुखता से उठाने की पहल बताया जा रहा है। राहुल गांधी इससे पहले भी छात्र संगठनों और युवाओं के बीच जाकर शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। आगामी कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस युवाओं से जुड़ाव बढ़ाने और उनके मुद्दों को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की तैयारी में है।

सीएम योगी का सख्त संदेश– बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, अभद्र टिप्पणी करने वालों पर होगी कार्रवाई

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के सम्मान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि

बेटियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा,'बेटी बेटी होती है, हम उस संस्कार में पले हैं जहां गांव की बेटी को सबकी बेटी माना जाता है।' सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं और बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी की बेटी, बहन या परिवार के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग समाज की मर्यादा के खिलाफ है। ऐसे मामलों में बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखें और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विचारों की असहमति हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर शासन ने गठित की SIT , १५ दिन में देनी होगी अंतिम रिपोर्ट

लखनऊ।'' श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया है। शासन द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति को पूरे मामले की जांच कर निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। SIT को निर्देश दिया गया है कि वह ''७ दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट'' और''१५ दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट'' शासन को सौंपेगी। जांच समिति में तीन वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया हैं ''विजय विश्वास पंत(IAS),मंडलायुक्त लखनऊ'' अध्यक्ष''किरन एस (IPS), आईजी रेंज'' सदस्य ''नील रतन, विशेष सचिव वित्त'' सदस्य शासन ने समिति को मामले की गंभीरता को देखते हुए तथ्यों की गहन जांच करने और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। SIT जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सम्पादकीय

प्रक्रिया ही जब प्रताड़ना बन जाए

न्यूजक्लिक और खुर्रम परवेज के मामलों में अदालती फैसलों ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और श्प्रक्रिया को ही दंडश बना देने की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छह साल तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कथित यांत्रणा झेलने के बाद आखिरकार खोजी वेबसाइट श्न्यूजक्लिकश को न्याय मिला है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने न केवल इसके खिलाफ चल रहे मुकदमे को खारिज किया, बल्कि बेहद तल्ख और महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी कीं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि न्यूजक्लिक के खिलाफ जारी कार्यवाही न सिर्फ दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता पर मनमाना हमला तथा राजकीय शक्ति के दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लगाए गए ईडी के आरोपों को 'पूर्णतः गढ़ा हुआ और निराधार' ठहराते हुए अदालत ने माना कि एजेंसी दूर–दूर तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। संयोग नहीं है कि इसी दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय की ही एक अन्य पीठ ने जम्मू–कश्मीर के मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को पांच साल पुराने यूएपीए (**UAPA**) मामले में जमानत दे दी। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस मामले में फिलहाल मुकदमे की कार्यवाही शुरू होने की दूर–दूर तक संभावना नहीं है। इसलिए न्यायपीठ ने न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतें'जेल अपवाद और बेल नियमें'को लागू करना उचित समझा। ये दोनों ही फैसले देश में कानून के राज और न्याय की भावना के रोजमर्रा के स्तर पर हो रहे उल्लंघन को बेनकाब करते हैं। यहाँ बुनियादी सवाल किसी एक व्यक्ति या संस्था को सताने भर का नहीं है। सवाल व्यवस्था की नीयत और कार्यशैली पर है। यदि अभियोग पक्ष (**Prosecution**) के पास आरोपियों के खिलाफ अकाट्य और पुख्ता साक्ष्य होते हैं, तो वह न्यायिक कार्यवाही को तार्किक अंजाम तक पहुंचाकर कानूनन सजा दिलाने की तत्परता क्यों नहीं दिखाता? मामलों को सालों–साल लटकाए रखने का यह रवैया साफ संकेत देता है कि देश में अब 'प्रक्रिया को ही दंड' (**Process as Punishment**) बना देने का एक खतरनाक और अस्वीकार्य चलन स्थापित हो चुका है। कानून का भय दिखाने के लिए जांच की लंबी और जटिल प्रक्रिया को ही हथियार बना लिया जाता है। देर से ही सही, न्यूजक्लिक के मामले में इंसाफ हुआ, लेकिन इस श्अदालती जीतश की कीमत बहुत भारी रही है। न्याय मिलने से पहले वेबसाइट के संपादक और अन्य पदाधिकारियों को महीनों सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। एक सुचारू रूप से चल रही स्वतंत्र वेबसाइट मृतप्राय हो गई, दर्जनों पत्रकारों और कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं, और कई मीडियाकर्मियों के घरों पर छापे मारकर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूलधूसरित कर दिया गया। अदालत द्वारा आरोपों को निराधार मान लेने भर से इन जिंदगियों को हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। ऐसे में कुछ यक्ष प्रश्न देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका के सामने खड़े हैं। क्या अब वह समय नहीं आ गया है, जब दुर्भावना से ग्रसित होकर निराधार आरोप गढ़ने वाले और शक्तियों का दुरुपयोग करने वाले जांच अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए? जिन नागरिकों या संस्थानों की जिंदगी और साख को राज्य की मनमानी के कारण अपूरणीय क्षति पहुंचती है, क्या उन्हें उचित वित्तीय और सामाजिक मुआवजा देने का कानूनी प्रावधान नहीं होना चाहिए अदालतों के ये हालिया फैसले नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी के लिहाज से राहतकारी जरूर हैं, लेकिन ये एक गंभीर चेतावनी भी हैं। जब तक दुर्भावनापूर्ण अभियोजन (**Malicious Prosecution**) के खिलाफ सख्त कानून और जवाबदेही की व्यवस्था नहीं बनती, तब तक 'कानून का राज' केवल कागजों तक सीमित रहेगा और निर्दोष लोग इस अंतहीन प्रक्रिया की चक्की में पिसते रहेंगे।

आईटी क्षेत्र में एआई की दस्तक: मध्य वर्ग पर मंडराता नया संकट

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का नीतिगत बदलाव भारत के समूचे तकनीकी क्षेत्र, रोजगार परिदृश्य और मध्यवर्गीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरे की घंटी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन का यह बयान भारतीय रोजगार बाजार के लिए

एक बड़ी चेतावनी है कि कंपनी में अब जितने मानव कर्मचारी होंगे, उतनी ही संख्या में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एजेंट भी तैनात किए जाएंगे। कारपोरेट जगत के इस शीर्ष नेतृत्व का यह रुख किसी सामान्य तकनीकी बदलाव का संकेत नहीं, बल्कि इस बात का सीधा एलान है कि अगले कुछ वर्षों में मानव कर्मचारियों की जरूरत घटकर आधी रह सकती है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में शुरू हुआ यह नीतिगत बदलाव स्वाभाविक रूप से अन्य सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में भी दोहराया जाएगा, जिसके दूरगामी सामाजिक–आर्थिक परिणाम होने तय हैं। वर्तमान में भारत के आईटी उद्योग में ६० लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। यह क्षेत्र न केवल उच्च वेतनमान के लिए जाना जाता है, बल्कि यह देश के उपभोक्ता मध्य वर्ग की रीढ़ भी है। भारतीय कर प्रणाली में आयकर दाताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। ऐसे में, यदि इस क्षेत्र पर एआई की तलवार चलती है, तो इसका सीधा असर देश की क्रय शक्ति और मध्यवर्गीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। साल २००० के दशक की शुरुआत से भारत में यह भरोसा पुख्ता हुआ था कि इंजीनियरिंग की डिग्री एक सुरक्षित और शानदार करियर की गारंटी है। देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों का जो विशाल जाल फैला, वह इसी भरोसे की बदौलत था। लेकिन अब इस भरोसे की नींव हिलने लगी है। नए डिग्रीधारियों (फ्रेशर्स) के लिए रोजगार के अवसर पहले ही सीमित हो रहे थे, और अब यह संकट छंटनी के रूप में सामने आने लगा है। पिछले वर्ष खुद टीसीएस से करीब १२ हजार कर्मचारियों का निकाला जाना और अब चेयरमैन द्वारा इसे एक 'नीतिगत निर्णय' स्वीकार करना यह साफ करता है कि यह मंदी तात्कालिक नहीं, बल्कि ढांचागत है। यदि तकनीकी क्षेत्र में नौकरियों की संभावनाएं इसी तरह खत्म होती रहीं, तो इसका सीधा और बुरा असर देश के तकनीकी शिक्षा ढांचे पर भी पड़ेगा। बेशक, तकनीकी विकास के इस दौर में एआई से जुड़े कुछ नए और उच्च कौशल वाले रोजगार पैदा होंगे। लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों का रुझान बताता है कि एआई एजेंट दोहराव (**Repetitive**) वाले हर उस कार्य को करने में सक्षम और प्रशिक्षित होते जा रहे हैं, जिनमें अब तक इंसानी तकनीकी कौशल की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में गणित बिल्कुल साफ है। जितनी नौकरियां खत्म होंगी, उसकी तुलना में बेहद कम नए रोजगार पैदा होंगे। चिंतनीय पहलू यह भी है कि यह संकट केवल आईटी उद्योग तक सीमित नहीं रहने वाला है। बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे तमाम 'व्हाइट कॉलर' (दफ्तरों में काम करने वाले) क्षेत्रों में भी एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। एआई को अब तक केवल एक तकनीकी प्रगति के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि यह एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने जा रही है, जो हमारे मध्य वर्ग को सिकोड़ सकता है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए, जहां हर साल लाखों युवा कार्यबल में शामिल होते हैं, रोजगार का यह संकट एक बड़ी चुनौती है। नीति–नियंताओं और कॉर्पोरेट जगत को समय रहते इस पर विचार करना होगा कि इस तकनीकी क्रांति के बीच मानव श्रम की प्रासंगिकता और सामाजिक सुरक्षा को कैसे बचाया जाए, वरना 'डिजिटल इंडिया' की यह चमक कहीं रोजगार के मोर्चे पर अंधकार न ले आए।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारत के यशस्वी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी आज ७५ वर्ष की आयु में भी ५० वर्ष के व्यक्ति से अधिक ऊर्जा, फुर्ती और कार्यक्षमता के साथ राष्ट्रसेवा में निरंतर जुटे हुए हैं। भारतीय सनातन परंपरा में ७५ वर्ष की आयु को 'हीरक जयंती' का अत्यंत शुभ एवं सम्मानजनक पड़ाव माना जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर उनका राष्ट्र निर्माण के प्रति अटूट समर्पण और सक्रिय नेतृत्व पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संपूर्ण जीवन संघर्ष, परिश्रम, त्याग और राष्ट्रसेवा की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। संघर्ष की आग में तपकर कुंदन बने प्रधानमंत्री जी ने अपने कुशल नेतृत्व से भारत को वैश्विक मंच पर नई प्रतिष्ठा एवं पहचान दिलाई है। आज भारत विश्व समुदाय में आत्मविश्वास, सामर्थ्य और नेतृत्व क्षमता के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है तथा विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। श्री मौर्य ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, ऊर्जा सुरक्षा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत आज एक ऐसी उभरती हुई महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, जो विश्व शांति, सहयोग और मानव कल्याण की पक्षधर है। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रतिपादित 'युद्ध नहीं, बुद्ध' का संदेश भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों का परिचायक है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की निरंतर सेवा करते हुए सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहने का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। उनका प्रभावशाली नेतृत्व आज देश की प्रगति, सुशासन, आत्मविश्वास और वैश्विक सम्मान का पर्याय बन चुका है। विश्व के अनेक देशों द्वारा उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से अलंकृत किया जाना भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है। श्री मौर्य ने कहा कि 'तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें' की भावना को आत्मसात कर प्रधानमंत्री जी निरंतर राष्ट्रसेवा में समर्पित हैं। 'विकसित भारत– २०४७' का उनका संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा और भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध, शक्तिशाली तथा विश्वगुरु बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन एवं जन कल्याण के १२ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर वृहद गो संरक्षण केंद्र किशन तेजखेड़ा में कार्यक्रम आयोजित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने केंद्र सरकार के १२ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज यहां काकोरी के किशन तेज खेड़ा स्थित गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने गौ माता का पूजन–अर्चन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा उन्हें गुड़ एवं चना खिलाकर आमजन के मध्य गौसेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पशुधन मंत्री ने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत १२ वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। उनके नेतृत्व में पशुधन एवं दुग्ध विकास के क्षेत्र में अभिनव एवं प्रेरणादायी कार्य किये जा रहे हैं। जिसका सीधा लाभ किसानों, पशुपालकों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास'' का मंत्र देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा रहा है तथा ''एक भारत, श्रेष्ठ भारत'' की परिकल्पना को साकार कर रहा है।

श्री सिंह ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त पहल से पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं को गांव–गांव तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में मोबाइल वेटरनरी यूनिट जैसी अभिनव व्यवस्था उ०प्र० में संचालित है, जिसके माध्यम से पशुपालकों को उनके द्वार पर ही पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश को ५२० मोबाइल वेटरनरी यूनिट प्राप्त हुई हैं तथा टोल फ्री नंबर १९६२ पर कॉल करने पर निर्धारित समय के भीतर पशु चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस व्यवस्था से पशुओं के उपचार, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य संरक्षण को नई गति मिली है। इस अवसर पर वहां उपस्थित किसानों एवं पशुपालकों से अपील करते हुए श्री सिंह ने कहा कि दूध देना बंद करने वाली गायों को छुट्टा न छोड़ें, बल्कि उनकी समुचित देखभाल करें या स्थानीय गौशाला में उनको संरक्षित करें। गौवंश हमारी सांस्कृतिक धरोहर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। गौसंरक्षण केवल सामाजिक दायित्व ही नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण संकल्प भी है। सरकार गौवंश संरक्षण, संवर्धन एवं पशुपालकों की आय वृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को कृषि के समान महत्व प्रदान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन, पशुधन स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और रोजगार सृजन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। सरकार की विभिन्न योजनाएं ग्रामीण परिवारों, महिलाओं तथा छोटे पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य कर रही हैं। इस अवसर पर पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा पासवान ने कहा कि प्रदेश सरकार गोवंश संरक्षण एवं पशुपालकों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने गो संरक्षण को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए जनसहभागिता बढ़ाने पर बल दिया। इस अवसर पर माननीय मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वृहद गो संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया तथा गोवंश के लिए उपलब्ध भूसा, चारा, पेयजल एवं स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया एवं गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के १२ वर्षों की उपलब्धियों, पशुधन विकास एवं गोसंरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने गौसंरक्षण, पशुधन विकास तथा ग्रामीण समृद्धि के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम, विशेष सचिव श्री देवेंद्र पांडे, निदेशक प्रशासन एवं विकास, डा० मेमपाल सिंह, निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डा० राजेन्द्र प्रसाद सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पशुपालक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

वाराणसी में बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस निर्माण के लिए ०२ एकड़ भूमि रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान को उपलब्ध करायी जाएगी

लखनऊ। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जनपद वाराणसी में भूटान सरकार को बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस निर्माण के लिए ०२ एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। इससे संबंधित लीज डीड एग्रीमेंट पर पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह एवं अपर मुख्य सचिव पर्यटन श्री अमृत अभिजात की गरिमामयी उपस्थिति में रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान एवं पर्यटन विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर किया गया। भूमि हस्तांतरित करने संबंधी आवश्यक कार्यवाहियां पूरी कर ली गयी हैं। यह भूमि वाराणसी के अजइपुर, परगना कोलअसला तह०– पिंडरा में स्थित है। यह प्राइम लोकेशन की भूमि है। लीज डीड एग्रीमेंट (एमओयू) पर रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान की तरफ से श्रीमती ताशी पेल्डन, उप–मिशन प्रमुख रॉयल भूटानी दूतावास नई दिल्ली द्वारा हस्ताक्षर किया गया और श्री सांगे थिनले, चांसरी प्रमुख व सुश्री चिमी वांगमों, काउंसलर–वित्त, रॉयल भूटानी दूतावास गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। पर्यटन विभाग उ०प्र० की ओर से विशेष सचिव मृदुल चौधरी ने हस्ताक्षर किए तथा दो अधिकारियों ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए और अभिलेखों का आदान–प्रदान किया गया। यह लीज एग्रीमेंट ३० वर्षों तक के लिए किया गया है, जिसका वार्षिक किराया एक रूपया निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के प्रतिनिधियों का स्वागत एवं हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इस समझौते को जमीन पर उतारा जाएगा। भूटान से हमारे ऐतिहासिक और मधुर संबंध है। भारत और भूटान एक–दूसरे के अच्छे पड़ोसी है। इसके अलावा सारनाथ पहले से ही बौद्ध धर्म का एक प्रमुख प्रेरणा स्थल है। बौद्ध मंदिर एवं गेस्ट हाउस के निर्माण हो जाने से बौद्ध श्रद्धालुओं की

संख्या में काफी वृद्धि होगी। राज्य सरकार बौद्ध परिपथ के अंदर आने वाले संकिसा, कुशीनगर आदि बौद्ध स्थलों पर उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कर रही है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस कड़ी में शामिल है। जयवीर सिंह ने बताया कि उ०प्र० अपने गौरवशाली, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों तथा समृद्ध, प्रोंतिक संपदा के दृष्टि पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ प्रदेश है। जनपद वाराणसी में स्थित सारनाथ एक आध्यातिक, बौद्धिक एवं दार्शनिक स्थल है। इसके अलावा संग्रहालय भी बनाया गया है। ०२ एकड़ भूमि रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान को हस्तांतरित किए जाने से भारत और भूटान के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध और प्रगाढ़ होगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ–साथ विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटन पधारेंगे। उन्होंने लीज डील एग्रीमेंट के लिए भूटान सरकार को बधाई दी और कहा कि भारत हमेशा भूटान के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने इस मौके पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष २०१७ के बाद से जो भी एमओयू निष्पादित किए गए हैं, उनकी समीक्षा की जाए। इसके अलावा विजिट माई स्टेट अभियान को युद्ध स्तर पर संचालित किया जाए। इस मौके पर जापानी दूतावास की श्रीमती ताशी पेल्डन ने उ०प्र० सरकार एवं पर्यटन विभाग का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भूटान और भारत सरकार के संबंधों को और सु ढ़ बनाने में यह समझौता ज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य श्री अमृत अभिजात, महानिदेशक पर्यटन श्री वेदपति मिश्रा, विशेष सचिव पर्यटन श्री मृदुल चौधरी, निदेशक ईको–पर्यटन श्री पुष्पेंद्र कुमार के० पर्यटन सलाहाकार श्री जेपीसिंह, संयुक्त निदेशक श्री रावत, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी मुख्यालय श्रीमती मंजू चौधरी एवं पर्यटन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही

लखनऊ। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने लखनऊ के आशियाना में निर्माणाधीन उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद भवन का निरीक्षण किया। उच्च शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा निदेशालय के नवनिर्मित कैंप कार्यालय का भी उद्घाटन किया, जिससे विभागीय कार्यों में सुगमता आएगी और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को भवन निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने और परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उच्च शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह भवन उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने में एक महत्वपूर्ण आधारशिला होगा। योगी सरकार नई शिक्षा नीति–२०२० को प्रभावी ढंग से लागू करने, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद भवन के पूरा होने से नीति निर्माण, शैक्षिक योजना, अनुसंधान को बढ़ावा देने और संस्थागत समन्वय की गतिविधियों को गति मिलेगी। सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल शिक्षण केंद्रों के रूप में नहीं, बल्कि नवाचार, अनुसंधान, कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एम. पी. अग्रवाल, सचिव अमृत त्रिपाठी, निदेशक उच्च शिक्षा बी. एल. शर्मा सहित उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नवाचार व अनुसंधान को राष्ट्र निर्माण से जोड़ें युवा वैज्ञानिकः सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से नवाचार व अनुसंधान को राष्ट्र निर्माण तथा जनकल्याण से जोड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, उद्यम, आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। शनिवार को विज्ञान भारती के सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कोई भी अनुसंधान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य आर्थिक उन्नयन, लोककल्याण और भारत को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि विज्ञान भारती का सातवां राष्ट्रीय अधिवेशन ज्ञान की पावन धरा काशी में आयोजित हो रहा है, जिसमें १३०० से अधिक प्रतिनिधि पंजीकरण करा चुके हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना मदन मोहन मालवीय की साधना का परिणाम है और इसकी स्थापना का उद्देश्य काशी को उसकी प्राचीन ज्ञान–विज्ञान की पहचान दिलाना था। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय ज्ञान परंपरा, आधुनिक विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार का समन्वय भारत को विकसित राष्ट्र बनाने तथा विश्व मंच पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक विज्ञान की प्रभावी यात्रा लगभग ४००–५०० वर्षों की है, जबकि भारत हजारों वर्षों से ज्ञान, विज्ञान और नवाचार का केंद्र रहा है। २००० वर्ष पूर्व वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी ४४–४५ प्रतिशत थी। विदेशी आक्रमणों के कठिन दौर में भी यह २४–२५ प्रतिशत बनी रही, लेकिन स्वतंत्रता के समय घटकर १.५ से २ प्रतिशत रह गई। भारत का किसान केवल किसान नहीं था, बल्कि वह इन्वेंटर और नवाचारी भी था। प्राकृतिक खेती, पशुपालन और भूमि की उर्वरता बनाए रखने की पारंपरिक व्यवस्थाएं उसकी वैज्ञानिक सोच का प्रमाण थीं। उन्होंने श्रीमद्‌भागवत गीता का उल्लेख करते हुए कहा कि कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य भारतीय अर्थव्यवस्था की परस्पर जुड़ी हुई व्यवस्थाएं थीं लेकिन समय के साथ हम रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भर हो गए और अपनी मूल परंपराओं से दूर होते चले गए। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय व्यापारी केवल व्यापार नहीं करता था, बल्कि देश को जोड़ने का कार्य करता था। भारतीय कारीगर भी केवल शिल्पकार नहीं बल्कि उद्यमी था, जिसने भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया। आज भी आत्मनिर्भरता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वही म डल प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके प्रयोगों ने यह सिद्ध किया था कि पौधों में भी संवेदनशीलता और चेतना होती है। यदि एक पौधा

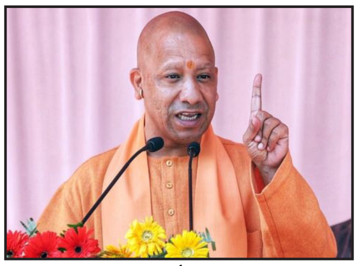

सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार का प्रभाव समझ सकता है तो समाज पर नकारात्मक सोच के प्रभाव का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। विदेशी आक्रांताओं, वामपंथी विचारधाराओं और भारत–विरोधी प्रवृत्तियों ने लंबे समय तक भारतीय ज्ञान परंपरा और गौरव को कमतर दिखाने का प्रयास किया, जिससे समाज अपनी जड़ों से दूर होता गया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने बचपन की स्मृतियां साझा करते हुए कहा कि उत्तराखंड के गांव में उनकी माता छोटी–छोटी क्यारियों में सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित करती थीं। भारतीय जीवन पद्धति का हर पक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ है। रसोई में हल्दी और मसालों के उपयोग से लेकर दैनिक जीवन की अनेक परंपराओं तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है। कोविड महामारी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने १४० करोड़ की आबादी के बावजूद महामारी का प्रभावी मुकाबला किया। यह भारतीयों की प्रोंतिक प्रतिरोधक क्षमता और पारंपरिक जीवनशैली का परिणाम था। गांवों में मार्च से अक्टूबर तक पशुओं को खेतों में बांधने की परंपरा प्राकृतिक और गो–आधारित खेती का उत्कृष्ट उदाहरण थी। इस व्यवस्था के कमजोर होने के साथ खेती की लागत बढ़ी, भूमि की उर्वरता प्रभावित हुई और कृषि संकट गहराया। उन्होंने कहा कि वर्ष २०१७ में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में परंपरागत उद्यमों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना के माध्यम से कारीगरों को तकनीक, डिजाइन, पैकेजिंग और मार्केटिंग से जोड़ा गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश का निर्यात ८६ हजार करोड़ रुपये से बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। वर्तमान में प्रदेश में ६६ लाख एमएसएमई इकाइयां संचालित हैं, जिनमें लगभग तीन करोड़ लोग कार्यरत हैं तथा बेरोजगारी दर तीन प्रतिशत से नीचे आ गई है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने तक्षशिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेदाचार्य जीवक का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु ने जीवक को ऐसी वनस्पति खोजने का निर्देश दिया जिसमें औषधीय गुण न हों। लंबे समय तक खोज के बाद जीवक ने बताया कि उन्हें ऐसी कोई वनस्पति नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिक दृष्टि का प्रमाण है, जिसमें प्रकृति के प्रत्येक तत्व में उपयोगिता और अनुसंधान की संभावनाएं देखी जाती हैं। युवा वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कृषि, चिकित्सा, तकनीक, एमएसएमई, उद्यम और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवाचार के अनगिनत अवसर मौजूद हैं। उन्होंने विज्ञान भारती को सुझाव दिया कि प्रत्येक अधिवेशन के साथ नवाचार प्रदर्शनी आयोजित की जाए, अधिवेशन से पहले नवाचार प्रतियोगिताएं कराई जाएं और उत्कृष्ट शोधकर्ताओं एवं नवाचारकर्ताओं को मंच पर सम्मानित किया जाए। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालयों तथा अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शोधकर्ताओं को अपने नवाचारों का प्रस्तुतीकरण करने का अवसर उपलब्ध कराया जाए।

समर इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत विधि छात्रों ने डीएलएसए एवं एलएडीसीएस कार्यालय का भ्रमण किया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा आयोजित समर इंटर्नशिप कार्यक्रम–२०२६ के अंतर्गत विभिन्न विधि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के १२८ विधि छात्र–छात्राओं ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (**LADCS**), लखनऊ का भ्रमण किया। कार्यक्रम के दौरान इंटर्न्स को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली,

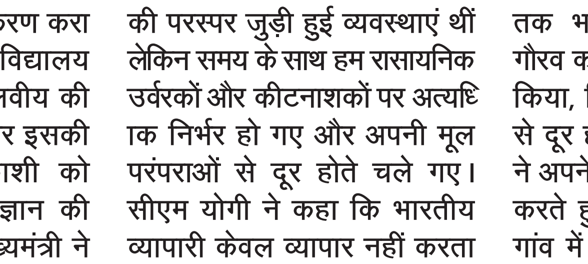

निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालत, पूर्व वाद मध्यस्थता, पीड़ित प्रतिकर योजना तथा विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की संरचना एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभियुक्तों को उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी अवगत कराया गया। इस अवसर पर उप सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ श्रीमती शालीन मिश्रा ने विद्यार्थियों को विधिक सेवा संस्थाओं की भूमिका, न्याय तक समान पहुंच तथा समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि विधि छात्रों को न्याय व्यवस्था की जमीनी कार्यप्रणाली से परिचित कराना समय की आवश्यकता है। मुख्य विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता (**Chief Legal Aid Defense Counsel**), श्री अरुण मिश्रा ने इंटर्न्स को लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की कार्यप्रणाली, आपराधिक मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था तथा अभियुक्तों के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एलएडीसीएस व्यवस्था न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को व्यावहारिक विधिक ज्ञान प्रदान करते हैं तथा उन्हें समाज के प्रति उत्तरदायी एवं संवेदनशील विधिक पेशेवर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने इंटर्न्स को निःशुल्क विधिक सहायता व्यवस्था, लोक अदालत एवं डीएलएसए की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में इंटर्न्स ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे तथा विधिक सेवा संस्थाओं के कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अंत में विद्यार्थियों ने इस भ्रमण को ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी बताया।

विवाद हुआ रंजिश हुई और फिर एक हत्या

लखनऊ। अपडेट–बागपत के बड़ौत में कल सोहनलाल अग्रवाल और उनके बेटे विकास की हत्या के बाद भाग रहे गैंगस्टर वरुण लुहारी को भीड़ ने खींच लिया

और बलकटी से प्रहार कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. बताया जाता है कि वरुण को गोली भी मारी गई. मेरठ के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। २०१५ तक सोहनलाल अग्रवाल और वरुण आपस में पार्टनर्स थे. विवाद हुआ रंजिश हुई और फिर एक हत्या हुई. वरुण इस मामले में हिस्ट्री सीटर था और फिर गैंगस्टर में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई उसका मकान कुर्क कर लिया गया वह आजकल देहरादून में शिफ्ट था और कल अपने केस की तारीख में बागपत आया था. इस दौरान वरुण ने क अग्रवाल फैमिली पर हमला किया. सोहन और उसके बेटे विकास की हत्या के आरोपी वरुण के पिता बाबूलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है बाकी बदमाशों की तलाश में पुलिस १० टीमें यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड में दबिशें दे रही है.

यूपी में निपुण भारत मिशन को मिलेगी नई रफ्तार, जुलाई में ३३ केंद्रों पर होंगी 'निपुण संकल्प कार्यशालाएं'

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों की आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने के लिए निपुण भारत मिशन को नई गति देने जा रही है। इसके तहत जुलाई माह में प्रदेशभर में 'निपुण संकल्प कार्यशालाओं' का आयोजन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित होने वाली इन कार्यशालाओं में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार, सीखने के परिणामों में वृद्धि और प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश के ३३ केंद्रों पर ६ जुलाई से ३१ जुलाई २०२६ तक चलने वाली इन कार्यशालाओं में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, शैक्षणिक विशेषज्ञ और जिला स्तरीय टीमें शामिल होंगी। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में भाषा और गणित की बुनियादी दक्षताओं को विकसित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निपुण संकल्प कार्यशालाएं शैक्षणिक सत्र २०२६–२७ की प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने और विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर में वास्तविक सुधार सुनिश्चित करना है। कार्यशालाओं में निपुण विद्यालय लक्ष्य, निपुण २.०, बालवाटिका संचालन, डेटा आधारित अनुश्रवण और सीखने के परिणामों में सुधार जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। कार्यशालाओं में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, डायट प्राचार्यों, एआरपी, एसआरजी, डायट मेंटरों और जिला समन्वयकों को एक मंच पर लाकर विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने की रणनीति बनाई जाएगी। इस दौरान शैक्षणिक सत्र २०२६–२७ की अकादमिक योजना, विद्यालय स्तर की गतिविधियों, निपुण विद्यालय लक्ष्यों और शिक्षण व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। विभाग के अनुसार, कार्यशालाओं में परख (PARAKH) राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर सीखने के परिणाम बेहतर करने की योजना बनाई जाएगी। जिला, ब्ल क और विद्यालय स्तर पर वार्षिक लक्ष्य तय करने, उनकी नियमित समीक्षा और डेटा आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा कक्षा ३ से ५ तक लक्ष्य आधारित शिक्षण, कैच–अप शिक्षण, निपुण प्लस में प्रस्तावित सुधार, १० प्वाइंट टूलकिट और शिक्षक संदर्शिका आधारित संरचित शिक्षण पद्धति को प्रभावी बनाने पर चर्चा होगी। कार्यशालाओं में एआईपीएफएसएसी पोर्टल के प्रभावी उपयोग, बीईओ और एआरपी के बीच बेहतर समन्वय, शिक्षकों को प्रभावी फीडबैक देने और विद्यालय गुणवत्ता सुधार की कार्ययोजना पर भी चर्चा की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि इन कार्यशालाओं के माध्यम से प्रदेश के विद्यालयों में शैक्षणिक नेतृत्व को मजबूत किया जाएगा और बच्चों को बेहतर एवं परिणाम आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

कोतवाली में हुआ थाना समाधान दिवस का आयोजन

धौरहरा खीरी। शनिवार को कोतवाली परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित थाना दिवस में २३ शिकायती पत्र दर्ज हुए दूसरी तरफ थाना ईसानगर परिसर में नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस में १३ शिकायतें दर्ज हुई। जानकारी के मुताबिक शासन के निर्देश पर आयोजित थाना धौरहरा समाधान दिवस में एसडीएम धौरहरा शशीकांत मणि व प्रभारी निरीक्षक दिनेश शर्मा की मौजूदगी में २३ शिकायती पत्र भूमि संबंधी मामले दर्ज हुए। थाना परिसर ईसानगर में नायब तहसीलदार फिरोजाबाद अखिलेश मौर्या व थाना प्रभारी बृजेश सिंह के मौजूदगी में १३ भूमि संबंधी वाद दर्ज रजिस्टर हुए। इस दौरान नायब तहसीलदार फिरोजाबाद ने बताया कि एक शिकायत का स्थलीय निरीक्षण मेरे साथ थाना प्रभारी बृजेश सिंह ने किया व तीन शिकायतों में पुलिस व राजस्व की टीम रवाना की गई। इस दौरान संबंधित थाना क्षेत्रों के लेखपालों के साथ उप निरीक्षक गण व फरियादियों की मौजूदगी रही।

तपती गर्मी में लखीमपुर पालिका एवं मनॉल कॉलेज ने दी राहत की सौगात, अधिवक्ताओं को मिले शीतलता के दो कूलर

लखीमपुर खीरी। भीषण गर्मी के बीच सेवा और संवेदनशीलता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव एवं मनॉल कॉलेज के डायरेक्टर कपिल श्रीवास्तव ने जिला अधिवक्ता संघ, लखीमपुर खीरी को दो कूलर भेंट किए। न्यायालय परिसर में कार्यरत अधिवक्ताओं तथा न्याय की उम्मीद लेकर आने वाले आम नागरिकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह सराहनीय पहल की गई। कूलरों की उपलब्धता से न्यायालय परिसर में गर्मी से जूझ रहे अधिवक्ताओं और वादकारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर महेंद्र पाल सिंह, मथुरा प्रसाद, योगेश सक्सेना, अनूप कुमार तथा राजेश कुमार सहित जिला अधिवक्ता संघ के अनेक वरिष्ठ एवं सम्मानित अधिवक्ता उपस्थित रहे। सभी ने इस जनहितकारी सहयोग के लिए डॉ. इरा श्रीवास्तव और कपिल श्रीवास्तव के प्रति आभार व्यक्त किया। सामाजिक सरोकार और जनसेवा से जुड़ी यह पहल न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों के लिए राहत का संदेश लेकर आई है तथा सेवा भाव की एक प्रेरक मिसाल बन गई है।

भीषण गर्मी में शुद्ध पेयजल प्लांट देख रहे मरम्मत की राह

(मनोज मिश्र)

धौरहरा खीरी। गर्मी के मौसम में तहसील,थाना,बैंक व खरीददारी करने के लिए आने वाले आम नागरिकों को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लाखों रुपये खर्च करके नगरीय क्षेत्र में स्थापित किए गए वाटर प्लांट नगर प्रशासन की बदहाल स्थिति का शिकार होते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार का लाखों रुपए खर्च करके नगरीय क्षेत्र में स्थापित वाटर प्लांट रखरखाव और नियमित साफ–सफाई के अभाव में कई वाटर प्लांट केवल शोपीस के साथ गंदा व बदबूदार पानी देने को विवश है।इस मामले में स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर पंचायत प्रशासन द्वारा वाटर प्लांटों की नियमित सर्विसिंग और सफाई नहीं कराई जाती। कई स्थानों पर आरओ सिस्टम निष्क्रिय पड़े है और लोगों को बिना फिल्टर किया हुआ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। भीषण गर्मी के दौरान प्लांटों से निकलने वाला पानी भी गर्म रहता है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। कस्बे के नागरिकों का कहना है कि पानी में अक्सर दुर्गंध आती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं।इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। एक ओर प्रदेश सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने और जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है,तो वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत धौरहरा की लापरवाही इन योजनाओं की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है।लोगों का आरोप है कि साफ–सफाई और रखरखाव के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। जबकि स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि मौजूदा समय में सभी वाटर प्लांटों की तकनीकी जांच कराकर आरओ सिस्टम को दुरुस्त कराया जाए व नियमित साफ–सफाई और निगरानी सुनिश्चित की जाए,ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

बलरामपुर चीनी मिल गुलरिया ने सीएसआर योजना के तहत किसानों को बांटे कृषि यंत्र

लखीमपुर खीरी। **Balrampur Chini Mills Limited** की गुलरिया इकाई ने सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) योजना के तहत किसानों को अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र वितरित किए। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला गन्ना अधिकारी जितेंद्र कुमार मिश्र और इकाई प्रमुख योगेश कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर इकाई प्रमुख ने बताया कि वित्तीय वर्ष २०२६–२७ में किसानों की ॅषि क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से २१ लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके तहत किसानों को लेजर लेवलर, पावर वीडर और स्प्रेयर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती की लागत में कमी आएगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी और किसानों के उत्पादन एवं आय में वृद्धि होने की संभावना है। कार्यक्रम में मिल अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद रहे।

अखिलेश की बेटी के खिलाफ अपमानजनक, फर्जी पोस्ट करने के लिए तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साइबर अपराध पुलिस ने समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को निशाना बनाकर किये गये आपत्तिजनक व भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट प्रसारित करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सपा की अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव परवीन यादव ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला बृहस्पतिवार को सामने आया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अदिति यादव की छवि को धूमिल करने और सपा प्रमुख के परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपमानजनक व मनगढ़ंत सामग्री अ नलाइन साझा की गई थी। प्राध्यमिकी में भरत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव को नामजद किया गया है। शिकायत के अनुसार, नौ जून को भरत कुमार पटेल नाम के सोशल मीडिया पर एक खाते से कथित तौर पर अपलोड किये गये एक पोस्ट में अदिति यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ-साथ श्झूठे और भ्रामकश दावे शामिल थे। एक अधि

ाकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पोस्ट में उन्हें कथित तौर पर चोरी और आपराधिक गतिविधियों से जोड़ा गया तथा उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से एक संपादित तस्वीर भी पोस्ट की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सामग्री जानबूझकर गढ़ी गई थी और एक 'सम्मानित परिवार' को बदनाम करने व सार्वजनिक आक्रोश भड़काने के लिए प्रसारित की गई थी। उन्होंने दावा किया कि दो अन्य आरोपियों ने मूल पोस्ट के जवाब में अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट कीं। अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) विपिन ताडा ने बताया कि भरत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि लगाई गई धाराएं महिला की गरिमा का अपमान करने, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जालसाजी व आपत्तिजनक सामग्री के इलेक्ट्र निक प्रसारण के माध्यम से गोपनीयता का उल्लंघन करने से संबंधित हैं। टाडा ने बताया कि मामले की जांच साइबर अपराध थाने द्वारा की जा रही है। साइबर अपराध प्रभारी निरीक्षक सतीश यादव ने बताया कि अपलोड किये गये पोस्ट, उपयोग किए गए उपकरणों और इसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की फोरेंसिक जांच तथा खातों की डिजिटल ट्रेसिंग जारी है।

यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश, कानपुर और ललितपुर रहे सबसे अधिक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शनिवार को मौसम ने करवट लेते हुए पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों के अनेक जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी वर्षा आंकड़ों के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा रिक र्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर के अनकिंगघाट में सर्वाधिक ६७.६ मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा सीतापुर के भटपुरवाघाट में ४४.८ मिमी, कानपुर आईएएफ में ४२ मिमी तथा कानपुर प्रेक्षण केंद्र पर ३८.४ मिमी बारिश रिक र्ड की गई। फर्रुखाबाद के कायमगंज में ३६.१ मिमी तथा फतेहगढ़ सीडब्ल्यूसी केंद्र पर ३१.६ मिमी वर्षा हुई। सीतापुर के नैमिषारण्य में २६ मिमी, कन्नौज के तिर्वा में १७ मिमी, हरदोई वेधशाला में १४.४ मिमी तथा कन्नौज में १४.२ मिमी बारिश दर्ज की गई। छिबरामऊ में १३ मिमी, बाराबंकी के रामनगर और हरदोई तहसील में १०-१० मिमी वर्षा हुई। राजधानी लखनऊ में भी मौसम सुहावना रहा और अमौसी स्थित एयरपोर्ट क्षेत्र में ८.८ मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा सीतापुर में सात मिमी, मिश्रिख में छह मिमी तथा बिलग्राम में ५.२ मिमी वर्षा हुई। उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के मड़ावरा क्षेत्र में सर्वाधिक ४८ मिमी वर्षा रिक र्ड की गई। मथुरा के गोवर्धन में ३६ मिमी, आगरा के सीडब्ल्यूसी केंद्र पर ३७ मिमी तथा एटा और जलेसर में ३५-३५ मिमी वर्षा हुई। फिरोजाबाद जिले के जसराना में २६.४ मिमी, हाथरस के सादाबाद में २४ मिमी, बदायूं में २३ मिमी तथा शिकोहाबाद में २२ मिमी बारिश दर्ज की गई। फिरोजाबाद के टूंडला में २१ मिमी और अलीगढ़ में २०.६ मिमी वर्षा हुई। इटावा के ताखा और इटावा वेधशाला में क्रमशः २० मिमी और १५ मिमी, बुलंदशहर के सिकंदराबाद में १५ मिमी तथा नरौरा में १४.६ मिमी वर्षा रिक र्ड की गई। मैनपुरी, कासगंज, आगरा और हाथरस के विभिन्न क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों जैसे गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और मेरठ में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जबकि जालौन, शाहजहांपुर और बरेली के कुछ क्षेत्रों में केवल नाममात्र की बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय मौसमी प्रणाली के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं मध यम वर्षा का सिलसिला जारी रह सकता है। इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं किसानों के लिए भी यह बारिश लाभकारी साबित हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने तथा आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।

भाई ने की बहन की हत्या, कुएं में फेंका शव

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में प्रेमी के साथ गई बहन की एक युवक ने गला घोंट कर हत्या कर दी और शव को कुएं में डाल दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने आज यहां बताया कि थरियांव थाना क्षेत्र के हसवा गांव के जंगल में स्थित एक कुएं में शनिवार सुबह लोगों ने एक युवती का शव देखा। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ लग गई। सूचना पर थरियांव और खागा कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। युवती की पहचान के बाद पुलिस उसके घर पहुंची और भाई को हिरासत में लिया। पूछताछ में भाई ने बताया कि उसकी बहन कुछ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ भाग कर शादी कर ली थी जिस पर वह उसके घर गया और उसे बुला कर घर ले जाने के बहाने रास्ते में उसकी हत्या कर शव कुएं में डाल दिया था।पुलिस ने बताया कि आरोपी भाई गुजरात में रहकर काम करता था और वह दो दिन पहले ही अपने घर आया था। हत्या करने के बाद वह फरार होने की फिराक में था तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

अमरोहा में जलभराव और बिजली संकट से जनजीवन प्रभावित

अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में तेज हवाओं के साथ हुई कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश ने नगर निकायों और प्रशासन की मानसून पूर्व तैयारियों की वास्तविकता उजागर कर दी। जिले के मंडी धनौरा, गजरौला, बछरायूं, हसनपुर और अमरोहा नगर क्षेत्रों में जलभराव, बिजली आपूर्ति बाधित होने और अव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुवार देर रात मौसम के अचानक बदले मिजाज के बीच तेज आंधी और भारी बारिश ने पूरे जिले को प्रभावित किया। कई स्थानों पर तेज हवाओं के कारण पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। हालांकि बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय निकायों की तैयारियों पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए। बारिश शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर विभिन्न नगर क्षेत्रों की सड़कें जलमग्न हो गईं। नालों और नालियों के ओवरफ्लो होने से गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा। कई स्थानों पर जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह विफल नजर आई। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को देर रात तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर वर्ष बड़े स्तर पर खर्च किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति में कोई सुधार दिखाई नहीं देता। महादेव मंदिर सरोवर से होकर गुजरने वाले बाढ़ खंड नाले और ड्रेनेज सिस्टम के अवरुद्ध होने के कारण निचले इलाकों में गंदा पानी घरों तक पहुंच गया। तेज आंधी और बारिश के चलते विद्युत आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई। सुरक्षा कारणों और तकनीकी खराबियों के चलते कई क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति बाधित कर दी गई। दर्जनों ट्रांसफार्मरों और विद्युत लाइनों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। परिणामस्वरूप अमरोहा जिले के कई हिस्से रातभर अंधेरे में डूबे रहे। लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से घरों में लगे इनवर्टर भी जवाब दे गए, जिससे लोगों को पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ा। शुक्रवार को भी कई क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सामान्य नहीं हो सकी। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। ऐसे में नागरिकों का कहना है कि यदि नगर निकाय सामान्य बारिश की स्थिति से प्रभावी ढंग से नहीं निपट पा रहे हैं, तो मानसून के दौरान संभावित गंभीर परिस्थितियों से निपटना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। बारिश के बाद उत्पन्न हालात ने एक बार फिर शहरी बुनियादी ढांचे, जल निकासी व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान और विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की है।

बारिश के बाद ढहा कच्चा मकान, मलबे में दबकर महिला की गई जान

मुरादाबाद। मुरादाबाद में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। कुंदरकी थाना क्षेत्र के रूपपुर गांव में भारी बारिश के बाद एक कच्चे मकान की छत ढह गई। इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के वक्त महिला नमाज अदा करने की तैयारी कर रही थी। रूपपुर गांव के रहने वाले फुरकान ने बताया कि शुक्रवार सुबह उनकी पत्नी नमाज पढ़ने की तैयारी कर रही थीं। इसी दौरान वह कपड़े लेने के लिए कमरे के अंदर गईं। तभी अचानक कमजोर हो चुकी कच्ची छत भरभराकर उनके ऊपर गिर पड़ी। हादसे के तुरंत बाद घर में चीख-पुकार मच गई। छत गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़ पड़े। लोगों ने बिना देरी किए राहत कार्य शुरू किया और भारी मशक्कत के बाद मलबे को हटाकर महिला को बाहर निकाला। हालांकि, मलबे में दबने और गंभीर चोटें आने के कारण महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि बीती रात क्षेत्र में भारी बारिश हुई थी, जिसके चलते मिट्टी की छत कमजोर होकर ढह गई।

घटना की सूचना मिलते ही कुंदरकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी दे दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पीड़ित परिवार को नियमानुसार जो भी सरकारी सहायता और मुआवजा होगा, वह जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा।

बाबा विश्वनाथ व मां गंगा ने पीएम मोदी को दिया गरीबों की पीड़ा समाप्त करने का सामर्थ्यः मुख्यमंत्री

वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कोई महान व्यक्तित्व नेतृत्व करता है तो वह देश असुरक्षा, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर महान बनता है। देश का नेतृत्व करने वाले महान व्यक्तित्व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी ने गरीबी देखी है, इसलिए बाबा विश्वनाथ व मां गंगा ने उन्हें गरीब की पीड़ा समाप्त करने की सामर्थ्य दी है। सीएम ने तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि २०१४ के बाद सपने हकीकत में बदल रहे हैं। जब संवेदनशील व्यक्तित्व नेतृत्व करता है तो संवेदना दिखती है। सीएम ने बाबा विश्वनाथ व मां गंगा से प्रार्थना की कि प्रधानमंत्री मोदी का यशस्वी नेतृत्व लंबे समय तक देश को मिलता रहे। सीएम योगी ने केंद्र सरकार के १२ वर्ष पूरे होने और निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक जनसेवा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल चौकाघाट में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में काशीवासियों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि बाबा विश्वनाथ धाम का हर व्यक्ति अभिभूत व गौरवान्वित है, क्योंकि १२ वर्ष पहले नए भारत को नेतृत्व देने के लिए काशी ने सांसद के रूप में मोदी जी का चुनाव किया। सही चुनाव जनमानस को सम्मान दिलाता है। देश मोदी जी के निर्वाचित पीएम के रूप में नए रिकॉर्ड को लेकर उत्साहित है, ऐसे में उनके साथ काशी का नाम भी जुड़ता है। सीएम योगी ने पीएम मोदी की सफलतम नेतृत्व क्षमता का अभिनंदन करते हुए काशीवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते भारत को देखा है। २०१४ के पहले की अव्यवस्था व भ्रष्टाचार ने वैश्विक मंच पर भारत की छवि को धूमिल कर दिया था। चारों ओर अविश्वास, आंतरिक–वाह्य सुरक्षा पर खतरा, हर तबके में निराशा व हताशा थी। पिछली सरकारों की गलत नीतियों ने उद्यमियों को श्रमिक बना दिया। श्रमिक पलायन, किसान आत्महत्या करने को मजबूर था। नौजवान के लिए नौकरी, रोजगार व दिशा भी नहीं थी। महिलाएं असुरक्षित थीं। हर योजना लागू होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। सीएम ने कहा कि २०१४ से पहले देश के १२० जनपद नक्सलवाद के शिकार थे। जब हम सीमा पर घुसपैठ का मुद्दा उठाते थे तो संसद में तत्कालीन सरकार कहती थी कि इस पर अधिक वक्तव्य नहीं देना चाहिए क्योंकि रिश्ते खराब हो जाएंगे। हमारे सैनिकों के साथ क्रूरता होती थी, लेकिन तत्कालीन सरकार मौन रहती थी। सीएम ने कहा कि २०१४ के बाद हर योजना गरीब, महिलाओं, नौजवानों व किसानों के लिए समर्पित है। किसान, कारीगर, हस्तशिल्पी, स्ट्रीट वेंडर्स, नवजात शिशु, अध्ययनरत युवा स्नातक, महिला–पुरुष, बुजुर्ग–नौजवान समेत हर तबके के लिए योजना बनाने और उनके उत्थान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखती है। सीएम ने कहा कि जनधन योजना के तहत हर गरीब का बैंक में खाता खुला। उस समय कांग्रेस व सपा हंसकर कहती थीं कि बेवकूफ बना दिया, लेकिन जब मोदी जी ने सरकारी सहायता में कट/कमीशन रोकने के लिए डीबीटी का इस्तेमाल शुरू किया तो यह सपा व कांग्रेस के मुंह पर तमाचा था। एक लाचार पीएम कहते थे कि १०० रुपये भेजता हूं और नीचे केवल १५ रुपये पहुंचते हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वह कहते हैं कि १०० रुपये भेजता हूं तो सीधे गरीब के खाते में जाते हैं। सीएम ने स्वच्छ भारत मिशन से आए परिवर्तन का जिक्र किया, कहा कि बच्चों की असमय होने वाली मौत तत्कालीन सरकारों को विचलित नहीं करती थी, लेकिन इस मिशन ने बच्चों की मौत पर विराम लगाया और नारी गरिमा की रक्षा की। १२ करोड़

गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए। ४ करोड़ परिवारों को देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। सीएम ने २०१४ के पहले बीमारी से गरीब की तिल–तिलकर होने वाली मौत का दर्द भी बयां किया। कहा कि संवेदनशील व्यक्तित्व जब नेतृत्व करता है तो संवेदना दिखती है। भारत में ६० करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। जब कोरोना से दुनिया पस्त थी, तब भी मोदी जी ने फ्री में टेस्ट की व्यवस्था की। ८० करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया गया। मोदी जी ने ग्रामीण अभिलेख के माध्यम से घरौनी योजना प्रारंभ की। देश में ३ करोड़ परिवारों को जहां उनका आवास था, वहां उसका मालिकाना अधिकार मिला। इसका सर्वाधिक लाभ महिलाओं को मिला। ३ करोड़ लखपति दीदी, १० करोड़ महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य हुआ। २५ करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का कार्य चमत्कारिक है। सीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ करते हुए कहा कि फोरलेन की कनेक्टिविटी से जाम की समस्या का समाधान हुआ। फ्लाईओवर, ओवरब्रिज आदि का कार्य फटाफट हुआ। जो काम ७० वर्ष में नहीं हुए, मोदी जी ने १२ वर्ष में काशी, प्रदेश व देश में वह करके दिखा दिया। आज देश में एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरकनेक्टिविटी की बेहतरीन सुविधा हुई है। भारत में जब से वायुसेवा आई होगी, तब से २०१४ तक जितने एयरपोर्ट बने, मोदी जी के आने के बाद १२ वर्ष में उससे दोगुने एयरपोर्ट बने। देश में पहले केवल ५ शहरों में मेट्रो थी। आज देश के २० शहरों और यूपी के ७ शहरों में यह सुविधा है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच संचालित है। सीएम ने कहा कि काशी रोपवे के माध्यम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया म डल दे रहा है। जिसे किसी ने नहीं पूछा, उसे आज सब पूज रहे हैं। पहले स्ट्रीट वेंडर्स की दुर्गति किसी से छिपी नहीं थी। गरीब पर चौतरफा मार थी, लेकिन आज पीएम स्वनिधि योजना में वाराणसी में ६० हजार वेंडर्स को प्रथम, २६,८०० को द्वितीय व ५ हजार वेंडर्स को तृतीय किस्त भी मिल गई। नगर निगम, औद्योगिक व सामाजिक संगठन नए वेंडिंग जोन बनाकर उनके व्यवसाय को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि मोदी जी का विजन दूरदर्शी है। टीम उसे लागू कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम, नमो घाट भव्य बन गए। संकरी गलियों के लिए जाने जाने वाले काशी की कनेक्टिविटी फोरलेन की हो गई। काशी व प्रदेश को नई पहचान मिल रही है। पहले लोगों के मन में धारणा थी कि यहां अराजकता, गुंडागर्दी होती थी, परंतु आज काशी व यूपी का नाम लेने पर लोग गले लगाते हैं। अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो गए। मां विंध्यवासिनी क रिडोर बन गया। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक–डेढ़ महीने तक रोज १५–२० लाख श्रद्धालु काशी आते थे। सीएम योगी ने कहा कि वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के नाम पर ट्रेन की अत्याधुनिक सुविधा मिल रही है। रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह दिखते हैं। आस्था, अर्थव्यवस्था, युवा, महिला, बेटी के जन्म से लेकर विवाह, पढ़ाई से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक की योजनाएं चल रही हैं। अब विधानसभा व लोकसभा में कम से कम ३३ फीसदी महिलाएं चुनकर जाएंगी। हर तबके को काम मिला और उनका उत्थान हुआ। सीएम ने कहा कि ऊर्जा का वैश्विक संकट छाया हुआ है। अमेरिका में महंगाई लगभग चार गुना बढ़ी है। अन्य देशों की हालत भी खराब है, लेकिन प्रधानमंत्री के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट में भी भारत नागरिकों के उत्थान की ओर अग्रसर है। यह तभी संभव होता है, जब नीयत होती है। काशी की गलियों में आमजन, उद्यमियों, स्ट्रीट वेंडर्स, व्यापारियों, खिलाड़ियों, युवाओं से मोदी जी की बातचीत योजना बनाने में सहायक होती है, जिसका लाभ पूरा देश लेता है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र 'दयालु', महापौर अशोक तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डॉ. नीलकंठ तिवारी, त्रिभुवन राम, डॉ. अवधेश सिंह, डॉ. सुनील पटेल, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल, जिलाध्यक्ष रामसकल पटेल, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी आदि मौजूद रहे।

शिक्षकों को जल्द मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

लखनऊ। प्रदेश के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को जल्द ही पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इसके लिए विकसित अ नलाइन पोर्टल का बीटा वर्जन परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। योजना के तहत पात्र शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार का लाभ मिलेगा। स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पात्र कर्मचारियों का डेटा एकत्र कर उसे त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में नाम, जन्मतिथि, आधार संख्या और

पारिवारिक विवरण में विसंगतियों के कारण कार्ड निर्गमन में दिक्कतें आती थीं। इसी को देखते हुए इस बार डेटा सैनेटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साचीज द्वारा विकसित डेटा कलेक्शन पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रितों का विवरण एक समान प्रारूप में संकलित किया जा रहा है। अब तक ३.५ लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटा एकत्र किया जा चुका है। डेटा सत्यापन पूरा होने के बाद लाभार्थियों के कार्ड जारी किए जाएंगे। कार्ड बनने के बाद आश्रित परिवार के सदस्य भी योजना के दायरे में आ जाएंगे। अर्चना वर्मा ने बताया कि परीक्षण के दौरान कार्ड निर्माण, लाभार्थी सत्यापन, अस्पतालों से समन्वय और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं की जांच की जा रही है। योजना लागू होने के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

CRPF जवान समेत पुलिसकर्मी पर ५ लाख की लूट और अपहरण का आरोप

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में अपहरण और लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि एक सीआरपीएफ जवान और लखनऊ पुलिस के एक सिपाही समेत अन्य लोगों ने दो व्यक्तियों का अपहरण कर असलहे के बल पर करीब ५ लाख रुपये लूट लिए। इस घटना में सरकारी वाहन के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, वृंदावन क लोनी निवासी दिवाकर सिंह और उनके साथी अनूप शुक्ला को कंपनी में निवेश के नाम पर १० जून को चिनहट क्षेत्र स्थित ग्लोबल इन होटल के पास बुलाया गया था। आरोप है कि वहां से उन्हें जबरन एक सरकारी गाड़ी में बैठाया गया और बाद में हथियारों के बल पर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों ने उनसे रुपये छीन लिए और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की। घटना में एक आरोपी के लखनऊ पुलिस में सिपाही होने की बात सामने आई है, जबकि दूसरा आरोपी सीआरपीएफ का जवान बताया जा रहा है। मामले में पीड़ितों की तहरीर पर चिनहट थाने में दो नामजद और चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण, डकैती समेत गंभीर ६ ाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।

मोदी युग में बदली भारत और यूपी की तस्वीरः सीएम योगी

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के १२ वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित मीडिया संवाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते एक दशक में भारत ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब, महिला, युवा और किसान को विकास की धुरी बनाकर ऐसी नीतियां लागू कीं, जिनसे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा भी नई ऊंचाइयों पर पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के माध्यम से बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक माहौल तैयार हुआ, वहीं महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया। इससे महिलाएं अब देश के नीति निर्माण और कानून बनाने की प्रक्रिया में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर दिया। मुद्रा योजना के माध्यम से लाखों युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। वहीं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के जरिए पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को नई पहचान और आर्थिक मजबूती देने का प्रयास किया गया। सीएम योगी ने कहा कि किसानों के कल्याण को केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के करीब तीन करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में गन्ना किसानों को अब तक तीन लाख २२ हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल

रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब, महिला, युवा और किसान को देश की वास्तविक शक्ति बताते हुए विकास की मुख्यधारा में लाने का काम किया। इसी सोच का परिणाम है कि पिछले वर्षों में देश के लगभग २५ करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहल सामाजिक परिवर्तन का आधार बनी हैं। इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों परिवारों को बैंकिंग सुविधा, स्वच्छ ईंधन, स्वास्थ्य सुरक्षा और पक्का आवास उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिलना देश का सौभाग्य है। वर्ष २०१४ के बाद भारत ने जिस गति से प्रगति की है, उसका प्रभाव देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आज वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत और प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। इस अवसर पर यूपी भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को नई पहचान दी है। जनधन खातों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था के माध्यम से सरकारी योजनाओं में होने वाले लीकेज को प्रभावी ढंग से रोका गया है। अब योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और जनता का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार 'नागरिक देवो भवः' की भावना के साथ कार्य कर रही हैं। सरकार ने आम नागरिक को विकास प्रक्रिया का सहभागी बनाया है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था, आधारभूत संरचना और निवेश के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित कर चुका है।

‘काला हिरण’ फिल्म विवादः हाईकोर्ट पहुंचे सलमान खान

मुम्बई। अभिनेता सलमान खान ने फिल्म 'काला हिरण' द बैटल फ र लेगेसी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अदालत में स्थायी और अंतरिम निषेधाज्ञा की याचिका दायर की है, जिसमें फिल्म के निर्माण, प्रचार और वितरण पर रोक लगाने की मांग की गई है। सलमान खान ने अपनी याचिका में अमित जानी, जानी फायरफ क्स फिल्म्स, भारत श्रीनाते, अक्षय पांडेय समेत अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ–साथ अज्ञात पक्षों को भी शामिल किया है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि इन सभी को फिल्म से जुड़े किसी भी प्रकार के निर्माण, वित्तपोषण, निर्देशन और प्रचार कार्य से रोका जाए। अभिनेता का आरोप है कि फिल्म का पोस्टर और प्रचार वाले कंटेंट उनके

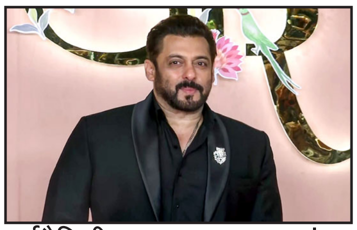

पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करती है। उनका कहना है कि उनके नाम, छवि और सार्वजनिक पहचान का उपयोग बिना अनुमति के व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा है, जो कानूनी रूप से गलत है। यह फिल्म १९९८ के चर्चित काला हिरण शिकार मामले और उससे जुड़े घटनाक्रमों पर आधारित बताई जा रही है। फिल्म को जानी फायरफ क्स फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है और इसका निर्देशन भरत एस. श्रीनाते ने किया है। हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया था, जिसमें अपराध और न्याय से जुड़ी कहानी की झलक दिखाई गई है। सलमान खान की कानूनी टीम ने पहले ही फिल्म निर्माताओं को नोटिस भेजा था। नोटिस में कहा गया था कि यह फिल्म उनके व्यक्तिगत अधिकारों और छवि को प्रभावित कर सकती है। साथ ही, यह भी उल्लेख किया गया कि मामला अभी राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर आधारित फिल्म का निर्माण और प्रचार कानूनी रूप से संवेदनशील मुद्दा है। विवाद के बीच निर्माता अमित जानी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नोटिस के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां और दबाव का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें हजारों मैसेज और फोन क ल मिले हैं। अमित जानी ने कहा कि यदि सलमान खान को कानूनी लड़ाई लड़नी है तो वह अदालत में लड़ें न कि धमकियों के जरिए दबाव बनाया जाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह फिल्म बिश्नोई समुदाय के संघर्ष और १९९८ की घटना पर आधारित है।

‘हैप्पीएस्ट बर्थडे डिशू’, दिशा पाटनी को आयशा श्रॉफ ने दी जन्मदिन की खास बधाई

मुम्बई। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी शनिवार को अपना ३४वां जन्मदिन मना रही हैं। उनका जन्म १३ जून १९९२ को यूपी के बरेली में हुआ था। उनके जन्मदिन पर लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्र फ ने अभिनेत्री को खास बधाई दी है। दिशा पाटनी के जन्मदिन पर आयशा श्र फ ने सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला संदेश साझा किया है। दिशा के लिए अपना प्यार जाहिर करने के साथ–साथ, आयशा ने यह भी वादा किया कि वे दोनों साथ में और भी कई यात्राएं करेंगी। टाइगर की मां ने इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने उनकी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "हैप्पीएस्ट बर्थडे डिशू!!! भगवान तुम पर कृपा बनाए रखे!! दिशा पाटनी।" तस्वीरों में दोनों कैमरे के लिए पोज देते हुए मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें उनके बीच के गहरे रिश्ते को बखूबी दिखाती हैं। कमेंट सेक्शन में अभिनेत्री ने लिखा आउ, लव यू मेरी आंटी, मुझे हमारी साथ की यात्राएं याद आती हैं। जवाब में आयशा ने कहा, "दिशा पाटनी चलो इस साल ऐसा बहुत कुछ करते हैं!! दिलचस्प बात यह है कि दिशा पाटनी का टाइगर श्रॉफ की मां आयशा श्र फ और बहन कृष्णा श्रॉफ के साथ बहुत अच्छा और करीबी रिश्ता है। बता दें कि दिशा और टाइगर को लेकर कई वर्षों तक अफवाहें रही हैं, फिर २०२२ में चुपचाप अलग हो गए। उस दौरान, उन्हें अक्सर इवेंट्स, छुट्टियों और पारिवारिक समारोहों में साथ देखा जाता था। हालांकि बहुत सारी अटकलें लगाई जाती थीं, लेकिन दोनों एक्टर्स ने हमेशा एक–दूसरे को "अच्छा दोस्त" कहा या किसी भी बात की सीधे तौर पर पुष्टि करने से बचते रहे।

टाइगर श्र फ से ब्रेकअप के बाद भी दिशा पाटनी ने कृष्णा श्रॉफ के साथ अपना अच्छा और दोस्ताना रिश्ता बनाए रखा है। सिद्धार्थ कन्नन के शो में कृष्णा ने दिशा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा था कि उनकी दोस्ती आज भी मजबूत है, भले ही दिशा अब उनके भाई के साथ रिश्ते में नहीं हैं। कृष्णा ने कहा था आज के समय में, जब महिलाएं एक–दूसरे को नीचा दिखाने में पीछे नहीं होतीं, वह (दिशा) और मैं एक–दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वे ऐसी इंसान हैं जो हर स्थिति में मेरे साथ खड़ी रहेंगी। उनमें किसी को जज करने की आदत नहीं है, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी के हर पहलू के बारे में उनसे खुलकर बात की है। वह ऐसी दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मैं भी उनके साथ रहूंगी। बता दें कि दिशा और टाइगर पहली बार म्यूजिक वीडियो "बेफिक्रा" में साथ नजर आए थे। बाद में उन्होंने २०१८ की फिल्म "बागी २" में भी साथ काम किया।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370

प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार

सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक

सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289

मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178

Email- adbhutsamachar @yahoo.in
adbhut_samachar @rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक